[Shri Nagen Saikia]

frequently. This results in victimisation of hundreds and thousands of people, and the State's industrial life is also affected adversely.

The second important reason is erratic power supply for which the production is badly affected. Another important reason is faulty pricing of products. The employees' Union of Namrup has clearly stated, as it c&me out in the Anam Tribune of 24th November, 1986, that:

> "Besides various other factors, unrealistic basis of achievement of capacity utilisation is one of the prime factors of losses. The rampant corruption at the top in collusion with the policy makers is contributing a lot to this ill-fate of the Corporation. "

The very objective of establishing the factories are going *to* be frustrated jn this way. I would like to draw the attention of the House to this matter and demand assurance from the Government that (1) not a single employee will be thrown out;
(2) the unproven obsolete machineries will be replaced by proven and modem ones;
(3) the factories of the HFCL will not be closed down; (4) the people at the helm of the affairs will be replaced by unbiased and efficient people with genuine love to the human and to the country. Fifthly, a thorough enquiry should be instituted to find out the evil hands. I caution the Government not to play with the lives of the people of the State. Thank you.

REFRENCE TO THE REPORTED DELAY IN STARTING GRADUATE DIPLOMA COURSE IN HINDI JOURNALISM BY THE INFORMATION AND BROADCASTING MINISTRY

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : माननीया, उपसभापति जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय जन-संचार संस्थान द्वारा हिन्दी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स शुरु करने में वित्त का पूर्ण प्रबंध हो जाने के बाद भी विलंब के कारणों पर विलम्बनीय लोक महत्व के उल्लेख करने की अनुमति दिये जाने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित और संपोषित भारतीय जन-संचार संस्थान इस वर्ष से हिंदी पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाला था । इसके लिए मंत्रालय ने दस लाख रुपये का प्रावधान भी सातवीं योजना काल के लिए कर दिया था । तत्कालीन पिछले हमारे सूचना मंत्रियों ने उस पाठ्यक्रम को 1986–87 सत्र में प्रारंभ किये जाने के बारे में संसदीय राजभाषा समिति और मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितियों को बराबर आश्वासन दिया कि यह कोर्स चालू किया जाएगा । तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता की संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, माननीय श्री एच०के० एल० भगत ने उक्त पाठ्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने की सार्वजनिक घोषणा की थी, किंतु संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही और उपेक्षा के कारण यह पाठ्यक्रम अभी तक प्रायम्भ नहीं हुआ है ।

तीन वर्ष लगभग बीत गये, लेकिन इस कोर्स के लिए किसी प्रकार की तैयारी जहां तक मुझे जानकारी है, अभी शुरु नहीं की गई । इससे साफ जाहिर होता है कि इस संस्थान के अधिकारियों का इरादा है कि इस पाठ्यक्रम को शुरु ही न किया जाए ।

अतएव इस सदन के माध्यम से आपके द्वारा मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि वह उक्त पाठ्यक्रम को इस वर्ष हर हालत में चालू करने का आदेश जारी करें क्योंकि संस्थान के पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि है ।

इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय जन-संचार संस्थान अपने जीवन का इक्कीसवां वर्ष पूरा कर चुका है और इस वर्ष इसे विश्वविद्यालय का दर्जा और मान्यता भी मिल रहीं है, फिर भी इसने हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया यद्यपि इस संस्थान के क्रिया-कलापों की

जांच के लिए नियुक्त मेहरा-मसानी समिति ने सार्वजनिक सिफारिश की थी कि भाषायी पत्रकारिता की शिक्षा का प्रबंध किये बिना संस्थान की प्रगति अवरुद्ध रहेगी और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। (समय की घंटी) मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि देश में हिंदी पत्रकारिता के विकास के लिए आवश्यक है कि इस संस्थान द्वारा हिंदी में तत्काल और धीरे-धीरे अन्य भारतीय भाषाओं में स्नात्कोत्तर पत्रकारिता की शिक्षा प्रारम्भ की जाए। नये और अपटुडेट आंकड़ों के अनुसार देश में हिंदी पत्र-पत्रकारिओं की की संख्या 6 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है और देश में साठ विश्वविद्यालयों से अधिक में हिंदी के माध्यम से पत्रकारिता की शिक्षा दी जा रही है। मुझे भी सौभाग्य दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की कक्षायें लेने का रहा है और पत्रकारिता पर ही मैंने डी. लिट का शोध निबंध दिया है और इसकी आवश्यकता इतनी है क्योंकि पत्रकार जो है, वह समाज रूपी नोका का खेवनहार होता है। पत्रकार सामाजिक चेतना का जागरूक अग्रदूत होता है और वह अपने विचारों द्वारा समाज की रुढ़ियों पर ज्वालामुखी पर बन कर फटता है और सारे समाज को नई चेतना देता है। इन विश्वविद्यालयों के छात्रों को हिंदी के माध्यम से ही स्नातकोत्तर शिक्षा पत्रकारिता से ही दी जा सकती है और उन्हें पत्रकारिता के व्यवसाय में रोजगार योग्य बना सकती है।

इस दष्टि से भारतीय जन-संचार संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर शिक्षा, डिप्लोमा कोर्स को इस वर्ष से प्रारम्भ किये जाने की योजना तत्काल लागू की जानी चाहिए और जनवरी 1987 में हर हालत में क्लास प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तत्काल कारगर कार्यवाही करनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

REFERENCE TO THE NEED TO EXEMPT ARTISTS, SPORTSMEN AND SCIENTISTS WINNING INTERNATIONAL AWARDS FROM PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES ETC.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Madam Deputy Chairman, as a nation, we are proud of our scientists, artists and sportsmen, who bring glory to the nation by making a mark in thier respective fields at the interantional level. We have artists, painters, musicians, scul-ptors who have won many international awairds and prizes,) We iave eminent scientists who due to their intellectual brilliance have brought name and glory to the nation by winning several international awards and prizes. We also have sportsmen who have excelled in their fields and have brought glory to the nation. Unfortunately, when they receive these interantional prizes and awards, they have to part with a sizeable sum as customs duties. In a few exceptional cases mostly relating to sportsmen and women, exemptions were made. I feel that a general exemption must be given to all our scientists, artists and sportsmen who bring glory to the nation, who exce] them in ihsir fields and because of whom, we ca, n ourselves feel very P[r]oud. Throu;;; h this special mention, may I request the Government to consider this serisonly and make a general exemption in case of all our artists, all our sportsmen, all our scientists who win international prizes and awards. Thank you.

REFERENCE TO THE REPORTED MOVE TO CONVERT HEALTH SERVICES IN PUBLIC HOSPITALS INTO A PRODUCTIVE INDUSTRY BY UTTAR PRADESH GOVERNMENT

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, 1 wish to draw the attention of the hon. Members of this august House as well as the Government to a very important matter and a very serious situation, arising out of a recent decision of the Medical and Health Department of the U. P. Government according to which th$_e$ service charges in Government hospitals have been increased. Till